दृष्टि The Vision

drishti

GENERAL STUDIES (Test–10)

निर्धारित समय: तीन घंटे *Time allowed: Three Hours*	DTVF/22 (J-A)–M–**GSM (M-I)-2210**	अधिकतम अंक: 250 *Maximum Marks: 250*

Name: Amit kumar yadav **Mobile Number:** ____________

Medium (English/Hindi): ____________ **Reg. Number:** ____________

Center & Date: ____________ **UPSC Roll No.** ***(If allotted)*****:** ____________

प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

इसमें बीस प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में छपे हैं।

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।

प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:

There are ***TWENTY*** *questions printed both in* ***HINDI*** *and* ***ENGLISH****.*

All the questions are compulsory.

The number of marks carried by a question is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

केवल मूल्यांकनकर्त्ता द्वारा भरा जाए *(To be filled by Evaluator only)*

Question Number	Marks	Question Number	Marks
1.		11.	
2.		12.	
3.		13.	
4.		14.	
5.		15.	
6.		16.	
7.		17.	
8.		18.	
9.		19.	
10.		20.	
Grand Total (सकल योग)			

____

मूल्यांकनकर्त्ता (हस्ताक्षर)

Evaluator (Signature)

____

पुनरीक्षणकर्त्ता (हस्ताक्षर)

Reviewer (Signature)

drishti | दृष्टि The Vision

Feedback

1. Context Proficiency (संदर्भ दक्षता)
2. Introduction Proficiency (परिचय दक्षता)
3. Content Proficiency (विषय-वस्तु दक्षता)
4. Language/Flow (भाषा/प्रवाह)
5. Conclusion Proficiency (निष्कर्ष दक्षता)
6. Presentation Proficiency (प्रस्तुति दक्षता)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

1. विधियाँ परिवर्तन की शक्तिशाली साधन सिद्ध हो सकती हैं। लेकिन जल्दबाजी में निर्मित विधियाँ मंशा अनुरूप कार्य नहीं करतीं और नेक मंशा से बनी विधियाँ अप्रभावी रही हैं। इस संबंध में संसद की प्रभावहीनता के कारण विधि निर्माण में व्याप्त कमियों की चर्चा कीजिये एवं सुदृढ़ विधि निर्माण प्रक्रिया के लिये उपाय सुझाइये। (150 शब्द) 10

Laws can be powerful instruments of change. But badly made ones do not work as intended and well-intentioned ones are ineffective. In this regard, discuss lacunae gripping the law-making due to ineffectiveness of Parliament and suggest measures for robust law-making process. (150 words) 10

विधियां देश की सामाजिक आर्थिक बदलावों की प्रेरक है। यह देश में सकारात्मक प्रवृत्तियों के विकास का माध्यम है, किंतु अध्यादेश व संसद में बहुमत का दुरुपयोग विधि निर्माण प्रक्रिया को कमजोर करता है।

भारत में विधि निर्माण का दायित्व विधायिका को है, जबकि क्रियान्वयन का अधिकार कार्यपालिका का है।

जल्दबाजी मे निर्मित विधियों की चुनौतियां

- बहुमत का दुरुपयोग,
- पर्याप्त विचारविमर्श का अभाव
- विधियों मे व्याप्त कमजोरियों पर प्रकाश नही पड़ता, फलत: क्रियान्वयन में बाधा आती है।
- संसदीय कार्यप्रणाली गिरावट आती है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

- कृषि कानूनों के निर्माण में जल्दबाजी से संघर्ष की स्थिति सामने आयी, फलतः वापस लेना पड़ा।
- जनता का संसदीय कार्यप्रणाली पर विश्वास कम होता है।
- विपक्ष की कार्य गतिविधियां भी बाधा उत्पन्न करती हैं

विधि निर्माण के निम्न उपाय को अपनाया जा सकता है –

① विधि को लाने से पूर्व हितधारकों, ex नागरिक संगठन, कृषि संगठन से बातचीत व विमर्श किया जाए।

② संसद में विधियों पर्याप्त विचार-विमर्श

③ गंभीर विषयों को संसदीय समितियों के पास भेजा जाए।

④ सत्ता पक्ष व विपक्ष का संसदीय कार्यवाही में गरिमापूर्ण कार्यकरण किया जाए → इसके लिए आचार संहिता को प्रभावी बनाया जाए

संसदीय व्यवस्था में विधि निर्माण लोककल्याण को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से होना चाहिए, विधायिका के कार्यों का बहिष्कार किया जाता विधियों की प्रभावशीलता को सीमित करता है

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

2. न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया एक स्वतंत्र न्यायपालिका के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इस संबंध में कॉलेजियम प्रणाली का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द) 10

The process for the appointment of judges lies at the heart of an independent judiciary. In this regard critically analyze the collegium system. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारतीय संविधान शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है, जहां स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान के संरक्षण व नागरिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति ~~के लिए~~ आरंभ में सरकार द्वारा प्रस्तावित नामों को राष्ट्रपति की सहमति पर होती थी, किंतु 2nd जज वाद (सुझाव) में न्यायपालिका ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका को महत्वपूर्ण माना, इसी तरह 3rd जज वाद में कोलेजियम की अवधारणा सामने आयी।

कोलेजियम प्रणाली → मुख्य न्यायाधीश (CJI)
↳ 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश

- इसके तहत कोलेजियम जजों के नामों की सूची कार्यपालिका के पास भेजती है जिसकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा जजों की नियुक्ति की जाती है

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

सकारात्मक पक्ष → न्यायिक नियुक्ति में कार्यपालिका का हस्तक्षेप सीमित होता है
↳ न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है
↳ न्यायपालिका की शुचिता प्रभावी होती है

नकारात्मक पक्ष → यह शक्ति के पृथक्करण की नीति के विरुद्ध
↳ आलोचक अंकल जजेज की नियुक्ति की प्रक्रिया मानते हैं,
↳ कार्यपालिका की शक्ति सीमित
↳ अमेरिका व अन्य राष्ट्र में जजों की नियुक्ति कार्यपालिका की अनुशंसा पर होता है

↓ यह नियुक्ति की प्रक्रिया को अपारदर्शी बनाता है

न्यायपालिका की स्वतंत्रता एक अपरिहार्य तर्क है, किंतु न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता के लिए कोलेजियम द्वारा भेजे जा रहे नामों के साथ उनकी प्रभावशीलता व कार्यपद्धति का भी वर्णन होना चाहिए।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

3. एक सुदृढ़ और स्वतंत्र रूप से संचालित नागरिक समाज की उपस्थिति सफल और स्थिर लोकतंत्र की पहचान है। इस संबंध में नए भारत के निर्माण में नागरिक समाज की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (150 शब्द) 10

The presence of a strong and freely operating civil society is the hallmark of successful and stable democracies. In this regard critically examine the role of Civil society in making of new India. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

नागरिक समाज संगठन कुछ व्यक्तियों का स्वैच्छिक समूह है, जो लोकतंत्र में सरकार व नागरिक के बीच अंतर्क्रियाओं को प्रभावी बनाते हैं।

CSO →
- भारतीय किसान यूनियन
- FICCI
- ASSOCHAM
- छात्र संगठन
  - ABVP
  - NSUI

सकारात्मक भूमिका

- यह लोकतंत्र में जन प्रहरी के रूप में कार्य करते हैं, (वाचडॉग की भूमिका)
- जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाते हैं,
- लोकतंत्र में सरकारी नीतियों व कार्यों की समीक्षा कर प्रभावशीलता बढ़ाते हैं।
- किसान यूनियन व अन्य संगठन अपने हितों के अनुरूप नीति निर्माण के लिए दबाव डालते हैं

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

- पर्यावरण संगठनों पशुओं व वनों के संरक्षण को प्रभावी बनाया है जिनकी कोई आवाज नहीं है (Voice of Voiceless)
- वंचितों एवं महिलाओं के हितों को प्रभावी बनाते हैं।

नकारात्मक भूमिका

- कई बार विकास के कार्यों में बाधक बनते हैं-

① हिंसक विरोध प्रदर्शन व हड़ताल से लोक व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव
  - → CAA के विरोध में हिंसा
  - → कृषक कानूनों के विरोध में हिंसा

② सरकारी वित्त पोषण पर आधारित संगठन लोकतंत्र को कमजोर बनाते हैं

③ विदेशी अवैध फंडिंग व कालेधन को वैधानिक बनाने में संलिप्त हैं
  - → गृह मंत्रालय ने हाल ही में 10000 से अधिक संगठनों को प्रतिबंधित किया है

सशक्त नागरिक संगठन लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावी बनाते हैं, यह नागरिकों के अधिकारों को प्रभावी बनाने व नीतियों को धरातल पर उतारने के लिए महत्वपूर्ण माध्यम है

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

4. भारत की G20 अध्यक्षता की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत कितनी कुशलता से G20 में मौजूद अंतर को समाप्त करने के लिये रास्ते एवं साधन खोज सकता है और इसे साझा हित के मंच में रूपांतरित कर सकता है। टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द) 10

The success of India's G20 Presidency will depend on how deftly India can find paths and instruments to bridge the divides plaguing the G20 and turn it into a platform of shared interest. Comment. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

G-20 समूह विश्व की लगभग 80% GDP व 2/3 से अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है G-20 की 2023 की बैठक की अध्यक्षता भारत करेगा।

G-20 → USA, जापान, चीन, भारत, आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, तुर्की, जर्मनी, इटली - -

G-20 में मौजूद अंतर
  - → रूस-यूक्रेन युद्ध
  - → विश्व आपूर्ति श्रृंखला कमजोर हुई है

- विकसित व विकासशील देशों के बीच हित संघर्ष → WTO विवाद
  - → आर्थिक मुद्दों पर संरक्षणवादी नीतियों का प्रसार → USA ने भारत को GSP से बाहर कर दिया है
- चीनी आक्रामक नीतियां
  - → उत्पादों की डंपिंग के विरुद्ध संरक्षण उपाय।
- न्यूनतम कर कानूनों के संदर्भ में दृष्टिकोणों का अंतर ।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

- पर्यावरण संबंधी चुनौती से निपटने के लिए वित्त पोषण के संदर्भ में G छिकोणों की भिन्नता।
- एक स्थायी कार्यालय का अभाव

भारत की भूमिका –

- भारत G-20 का संस्थापक सदस्य रहा है,
- भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को प्रभावी बना सकता है
- जलवायु वित्त पोषण पर एकीकृत G छिकोण को व्यवहारिक बना सकता है,
- न्यूनतम कर (15% प्रस्तावित) को प्रभावी बना सकता है
- आतंकी वित्त पोषण व अवैध धनशोधन पर नियंत्रण को प्रभावी बना सकता है
- चीनी आक्रामक नीतियों के विरुद्ध एक मंच तैयार कर सकता है
- WTO विवादों का रचनात्मक हल निकाल सकता है

भारत एक सकारात्मक शांति सहअस्तित्व आधारित मानव केन्द्रित विश्व व्यवस्था के निर्माण में G-20 के मंच का सकारात्मक प्रयोग कर सकता है

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti दृष्टि The Vision

5. डेटा संरक्षण कानून में राज्य की निगरानी शक्ति के साथ-साथ व्यक्तिगत गोपनीयता को स्पष्ट करना चाहिये। चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

Data protection law should spell out individual privacy along with state surveillance power. Discuss. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी वाद (2017) में गोपनीयता को मूल अधिकार (Art-21) माना है, ऐसे में डेटा संरक्षण नागरिकों के अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो गया है,

डेटा संरक्षण कानून की आवश्यकता

- हाल ही में पेगासस जासूसी मामले से निजी डेटा के संरक्षण व राज्य की निगरानी के विवाद की स्थिति सामने आयी।
- आधार जैसे बायोमेट्रिक डेटा के व्यापक प्रयोग से डेटा संरक्षण कानून अपरिहार्य हो गया है
- आकाशा एयरलाइन्स के अनुसार हाल ही में नागरिकों के डेटा लीक का मामला सामने आया है,
  - डेटा लीक मामले में जवाबदेहिता व उत्तरदायित्व के लिए कानून आवश्यक है
- नागरिकों के DNA डेटा के प्रयोग संबंधी विधेयक के कारण भी डेटा संरक्षण

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

आवश्यक है।

- साइबर हमलों से सुरक्षा के लिए भी भारतों का संरक्षण आवश्यक है
- राज्य की निगरानी व जन अधिकारों के बीच संतुलन के लिए भी भारत आवश्यक है

आगे की राह – हाल ही में सरकार ने डेटा संरक्षण विधेयक को वापिस लेते हुए, नए रूप में पुनः पेश करने की बात की है।

डेटा संरक्षण के लिए **डेटा लोकलाइजेशन** की बात की जा रही है

→ राइट टू फारगेटन की संकल्पना पर भी विचार विमर्श हो रहा है

डेटा संरक्षण के संदर्भ में जस्टिस कृष्णा पैनल की अनुशंसा के आधार पर भारत द्वारा राज्य की शक्ति व नागरिकों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है

Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

6. दल-बदल विरोधी कानून गैर-सैद्धांतिक दल-बदल द्वारा लोकतंत्र के क्षरण के विरुद्ध सुरक्षा के लिये लाया गया था, हालाँकि यह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (150 शब्द) 10

Anti-defection law was brought to protect against the subversion of democracy by unprincipled defection, however, it has failed to achieve its objective. Critically Examine. (150 words) 10

लोकतंत्र की प्रभावशीलता के लिए संसदीय कार्यपालिका का स्थायित्व आवश्यक है, इसी परिस्थिति में आया राम गया राम की राजनीति पर नियंत्रण के लिए दल बदल विरोधी कानून, 1986 में लाया गया।

दल बदल कानून → प्रावधान (पद समाप्त होने के)
- निर्दलीय सदस्य द्वारा पार्टी की सदस्यता लेने पर
- मनोनीत सदस्य द्वारा 6 माह बाद पार्टी के सदस्य बनने पर
- खुद पार्टी से त्यागपत्र
- व्हिप का उल्लंघन करना
- पार्टी विरोधी गतिविधि

अपवाद → 2/3 सदस्यों का दल
↓
सदन के अध्यक्ष

सकारात्मक पक्ष

- सरकारों की स्थायित्व सुनिश्चित हुई,
- हॉर्स ट्रेडिंग की अवैध गतिविधियों में कमी आयी·
- सरकार की प्रभावशीलता बढ़ी,

Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

नकारात्मक पक्ष → ① यह सदस्यों के विशेषाधिकारों के विरुद्ध है

② अलोकमत को राजनीति का प्रभाव बढ़ा है।

③ सदन की विचारविमर्श की प्रक्रिया में गिरावट आयी है।

④ सदन में सदन के सदस्यों की अभिव्यक्ति पर पार्टी का नियंत्रण बढ़ गया है।

⑤

आगे की राह → सरकार स्थायित्व व विश्वास मत के प्रक्रिया के अतिरिक्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाए.

दल बदल करने वाले सदस्यों को कूलिंग आफ पीरियड के तहत 5 वर्ष तक पुनः चुनाव व मंत्री बनने से रोका जा सकता है,

↳ राजनीति के अपराधीकरण पर नियंत्रण

↳ जनता में जागरूकता का प्रसार

लोकतंत्र में सरकार का स्थायित्व लोककल्याण व आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, किंतु सदस्यों की विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी एक महत्वपूर्ण घटक है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

7. स्वच्छ भारत अभियान का व्यापक स्तर और दायरा इसे विश्व के सबसे बड़े स्वच्छता अभियानों में से एक बनाता है। इस संबंध में स्वच्छ भारत मिशन की सफलता का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (150 शब्द) 10

The sheer scale and scope of the Swachh Bharat Abhiyan makes it one of the largest cleanliness drives in the world. In this regard, critically evaluate the success of Swachh Bharat mission. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारत में स्वच्छता के प्रति सकारात्मक प्रवृत्ति व आदत बनाने के लिए सरकार ने 2014 में गांधी जयंती के दिन से स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ किया था।

स्वच्छ भारत मिशन की सफलता

- भारत के लगभग सभी गांव खुले में शौच (ODF) मुक्त घोषित हुए हैं
- PM आवास योजना के साथ शौचालय निर्माण को प्रभावी बनाया गया है
- ठोस एवं अपशिष्ट प्रबंधन को प्रभावी बनाया गया है
- नीति आयोग की स्वच्छता रैंकिंग से शहरों व राज्यों के बीच स्वच्छता के मामलों के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517

Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

- पंचायतों की स्वच्छता में भागीदारी प्रभावी हुई।
- इंदौर जैसा शहर स्वच्छता शहर के रूप में घोषित हुआ है

चुनौतियां
- ODF गांव व शहरों में अभी भी मे खुले शौच की प्रथा विद्यमान है
- भारत में केवल 60% ठोस अपशिष्ट का निपटान हो पाता है।
- स्वच्छता भी भारत अभी भी नागरिकों में विकसित नहीं हो पायी है
- पंचायतों की वित्तीय व प्रशासनिक स्थिति कमजोर है।
- जल अपव्यय की समस्या

सरकार ने स्वच्छता अभियान के माध्यम से स्वच्छता के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दिया है, इसके लिए स्वांगा के मॉडल के अनुरूप कानूनी प्रावधान से स्वच्छता प्रक्रिया और भी प्रभावी बनाया जा सकता है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

8. भारत-नेपाल ने 75 वर्ष पहले आधिकारिक राजनयिक संबंधों की शुरुआत के बाद से बहुआयामी और गहन संबंध साझा किये हैं। लेकिन इस संबंध में कई अंतर्विरोध भी देखने को मिले हैं। परीक्षण कीजिये। (150 शब्द) 10

India-Nepal has shared multidimensional and dense relations since the beginning of official diplomatic relations 75 years ago. Yet the relationship is marked by several contradictions. Examine. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारत व नेपाल के बीच रोटी बेटी का संबंध विद्यमान है जो सांस्कृतिक व आर्थिक एकता को बढ़ाता है

भारत नेपाल संबंध → नेपाल ऊर्जा उत्पादन से भारत आयातक है
- दोनों के बीच नागरिक का परागमन की संधि विद्यमान है
- दोनों देशों के नागरिकों को रोजगार नियोजन की छूट प्रदान की गई है
→ अरुण परियोजना का निर्माण भारत द्वारा किया जा रहा है
- BBIN समझौते को लागू किया जा रहा है
- सार्क का मुख्यालय काठमाण्डू में है
→ भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

- गोरखपुर व जानकी के बीच बस संचालन
- बिहार से नेपाल के बीच रेल संचालन को बढ़ावा दिया जा रहा है
  ↳ मैत्री वैक्सीन (कोरोना)

चुनौतियाँ

- चीन की आक्रमक नीतियों व उसके प्रति सुरक्षा प्रत्यक्ष की भिन्नता
  ↳ भारत चीन को प्रतिद्वंद्वी तो नेपाल सहयोगी मानता है
- सीमापार अवैध तस्करी
- परियोजनाओं को मिलने में देरी
- मधेसी संघर्ष व संविधान निर्माण के बीच तनाव
- भारत-नेपाल व्यापार में नेपाल को बड़ा घाटा है
- नेपाल में ऊर्जा उत्पादन प्रभावी नहीं हो पाया है

नेपाल व भारत के बीच संबंधों को सशक्त बनाने के लिए व्यापार संतुलन को प्रभावी बनाने के साथ परियोजनाओं के निर्माण की गति तीव्र करने की आवश्यकता है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

9. चीन अपने वैश्विक विस्तारवाद के एक भाग के रूप में दक्षिण एशिया में भारत के हितों को कमज़ोर कर रहा है। इस संदर्भ में चीन के प्रति-आधिपत्य और वृहत् क्षेत्रीय स्थिरता के लिये एक कदम के रूप में सार्क को पुनः सशक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

China as part of its global expansionism, is chipping away at India's interests in South Asia. In this regard discuss the need to reinvigorate SAARC as a step to counter-hegemonic China and for greater regional stability. (150 words) 10

चीन ने अपनी आक्रमक रणनीति के तहत दक्षिण एशियाई देशों को ऋण व अवसंरचना विकास में सहयोग दिया है जो भारत की सामरिक सुरक्षा की चुनौती है

चीन की चुनौती

- चीन द्वारा पाकिस्तान के साथ मिलकर CPEC का निर्माण भारतीय संप्रभुता का हनन है
- श्रीलंका में ऋण जाल की नीति से [illegible] व पर्ल आफ स्ट्रिंग नीति को प्रोत्साहन मिला है
- नेपाल व ल्हासा के बीच परिवहन साधनों का विकास भारतीय हितों के विरुद्ध है
- बांग्लादेश को [illegible] व सामरिक उपकरण उपलब्ध कराना भी भारत

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

के हितों के प्रतिकूल है

सार्क का प्रयोग

· भारत सार्क के माध्यम से चीन को प्रतिसंतुलित कर सकता है

· वृहद दक्षिण एशिया में सहयोग को प्रभावी बना सकता है

· यह चीन के ऋण जाल नीति को भी कमजोर कर सकता है

· [illegible] जैसी रणनीति BRI को कमजोर कर सकती है

भारत सार्क का प्रयोग दक्षिण एशिया के हितों को बढ़ाने के लिए कर सकता है

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

10. क्या आपको लगता है कि दूसरे राज्य पुनर्गठन आयोग (SRC) का समय आ गया है जो कई छोटे राज्यों के सृजन के साथ भारत के संघीय मानचित्र का पुनर्निर्माण कर सकता है? समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (150 शब्द) 10

Do you think that the time has come for a second States Reorganization Commission (SRC) that can redraw India's federal map, creating many smaller states? Critically Examine. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारतीय ~~संविधान~~ राज्यपुनर्गठन अधि. 1956 के द्वारा भाषायी आधार पर राज्यों के गठन को मान्यता दी गई थी,

जिसके फलस्वरूप 75 वर्षों में सशक्त राष्ट्र के रूप में भारत का उदय हुआ है किंतु नये राज्यों के गठन की मांग द्वितीय राज्य पुनर्गठन आयोग की भूमिका को उजागर करती है

· SRC की आवश्यकता

↳ बुंदेलखंड, गोरखालैंड जैसे राज्यों की मांग

↳ हाल ही में पृथक मिथिलांचल की मांग सामने आयी है

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

• इसीलिए नागालैण्ड व पूर्वोत्तर राज्य (त्रिपुरा) को एक राज्य बनाने के लिए

चुनौतियां

→ छोटे राज्यों के गठन से प्रशासनिक व वित्तीय चुनौतियां सामने आएंगी

→ राज्यों का गठन अलगाव को बढ़ावा दे सकता है

→ छोटे राज्यों में सरकार की स्थिरता पर निरंतर खतरा होता रहता है

पृथक राज्य के गठन के लिए प्रशासनिक व वित्तीय क्षमताओं का आकलन आवश्यक है इस संदर्भ में SRC का गठन कर राज्यों की व्यवहार्यता व क्षेत्रीय स्थिति की नए संभावनाओं को तलाशने की आवश्यकता है

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

11. "सहकारी संस्थाएँ देश के विकास में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं लेकिन शायद ही कभी नीति नियोजन के केंद्र बिंदु में होती हैं।" इस कथन के आलोक में सहकारी संस्थाओं के समक्ष विद्यमान विभिन्न समस्याओं और सहकारिता क्षेत्र के प्रबंधन के लिये एक नए केंद्रीय मंत्रालय के निर्माण के औचित्य पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

"Cooperatives play a vital role in the country's development but are seldom the focus of policy planning". In light of this statement discuss the various issues faced by Cooperatives and the rationale for the creation of a new Union Ministry to oversee the cooperatives sector. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

"विश्व बैंक के अनुसार सहकारी संगठन समान पृष्ठभूमि के कुछ व्यक्तियों का समूह है, जो लोकतांत्रिक तरीके से कार्यकरण कर विकास की गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं।"

सहकारी संगठनों की भूमिका → प्रबंधन { → सहकारिता अधि., 1950; → बैंकिंग अधि., 1949 }

↳ समावेशी विकास

↳ वंचित वर्गों तक वित्तीय पहुंच का प्रसार

↳ कृषि विपणन व खेती विपणन को प्रभावी बनाना → AMUL डेयरी

↳ सेवा जैसे महिला संगठनों ने महिला अधिकारों को प्रभावी बनाया है

↳ लिज्जत पापड़ संस्था ने उद्यमशीलता को प्रभावी बनाया है

↳ सहकारी बैंकों ने { शहरी, ग्रामीण } वित्तीय समावेशन का प्रसार किया है

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

सहकारी संस्थाओं की चुनौतियां → बाजार पहुंच सीमित है

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

1. सहकारिता राज्य सूची का विषय है, फलतः एकीकृत मॉडल कानूनों का अभाव है
   ↳ कार्यपद्धति को कमजोर बनाता है
2. RBI व सहकारी अधि० की दोहरी विनियामक स्थिति प्रबंधन को कमजोर बनाती है
3. मानव श्रम की कार्यकुशलता व प्रबंधकीय असमता → संगठनों को कमजोर करते हैं
4. सहकारी संगठनों पर राजनीतिक प्रभुत्व की स्थापना से उद्देश्य प्राप्ति संभव नहीं हो पा रही है।
5. भ्रष्टाचार की समस्या विद्यमान है
5. वंचित वर्गों व महिलाओं की भूमिका सीमित है।
6. वित्त तक पहुँच सीमित है

हाल ही में संघ सरकार ने एक पृथक सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है, जिसके फलस्वरूप

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti दृष्टि The Vision

निम्न लाभ हो सकते हैं_

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

1. एक मॉडल कानून के तहत सहकारिता का विकास
2. संघ व राज्यों के बीच समन्वय को बढ़ावा मिलेगा
3. हालही में RBI ने सहकारिता प्रबंधन से उत्पन्न किए हैं।
5. सहकारिता के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा, जिससे पूरी विकास तंत्र क्षेत्रों में प्रभावशीलता बढ़ सकती है।

चुनौतियां → राज्य सूची के विषय पर मंत्रालय बनाने से केंद्रीकरण को बढ़ावा मिल सकता है
↳ राज्य संघ विवाद सामने आ सकते हैं।

सहकारिता देश के समावेशी व सर्वांगीण विकास में प्रभावी भूमिका निभा सकता है, इसके लिए दोहरे विनियमन को समाप्त कर कुशल प्रबंधन तंत्र को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

12. "पंचायत की आवाज लोगों की आवाज है" और 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम यह सुनिश्चित करने के लिये सही दिशा में बढ़ाया गया कदम था कि लोगों की आवाज स्पष्ट रूप से सुनी जाए। हालाँकि इस अधिनियम के लागू होने के तीन दशक से अधिक समय के बाद भी पंचायत की आवाज में दृढ़ता की कमी है। टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द) 15

"The voice of the Panchayat is the voice of the people" and the 73rd constitutional amendment act was a step in the right direction to ensure that the voices of the people are heard loud and clear. However, even after more than three decades of the enforcement of this act, panchayat's voice lacks strength. Comment. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

लोकतंत्र के विकेन्द्रीकरण के क्रम में 73वें संविधान संशोधन, 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई।

पंचायतों का गठन
- भाग-9 के तहत पंचायतों का गठन
- 29 विषय पंचायतों को हस्तांतरित किए जाने का प्रावधान
- दलितों व जनजातियों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण
- महिलाओं को 33% आरक्षण

सकारात्मक पक्ष

- देश में पंचायतों के द्वारा लगभग 30 से 35 लाख जनप्रतिनिधि सामने आए, फलतः लोकतंत्र का पंचायत स्तर तक विस्तार हुआ,
- देश में महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला। फलतः महिला

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला

- ग्रामीण स्तर पर नियोजन को अपनाया गया,
- जनपद नियोजन समितियों ने ग्रामीण विकास को प्रभावी बनाया है
- केरल मॉडल के तहत 29 विषयों के हस्तांतरण व वित्तीय मॉडल ने सशक्तता को प्रभावी बनाया है
- समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ढूँढा गया, फलतः योजनाओं में प्रभावशीलता बढ़ी।
- वंचितों का सशक्तिकरण हुआ,
- जनता व सरकार के बीच गैप में कमी आयी।

फिर भी पंचायतों में निम्न चुनौतियां विद्यमान हैं

① अधिकांश राज्यों ने पंचायतों को सभी 29 विषय हस्तांतरित नहीं किए हैं,

② पंचायतों का पुरुषीकरण, मेलाकर जैसी

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

व स्थिति के आगे वित्तीय अक्षमता विद्यमान है

- पंचायतों को वित्त के लिए राज्य व केन्द्र पर निर्भर रहना पड़ता है
- पंचायतों के स्तर पर केन्द्रीय व राज्य योजनाओं के क्रियान्वयन के 80% से अधिक भाग होने से व्यापक नियोजन की गतिविधि बाधित रहती है
- पंचायतों का पंचायत अधिकारियों पर नियंत्रण का अभाव है
- पंचायत प्रतिनिधियों में पर्याप्त प्रशिक्षण व प्रबंधन क्षमता का अभाव विद्यमान है
- महिलाओं के संदर्भ में भी संरपंच पति की अवधारणा विद्यमान है

पंचायतों को प्रभावी बनाकर लोककल्याण को प्रभावी बनाया जा सकता है, इसके लिए केन्द्र व राज्य पर वित्त व प्रशासनिक नियंत्रण को पंचायतों तक हस्तांतरित किया जा सकता है

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

13. वर्षों से चुनावों के आयोजन और परिणामों की उनकी निष्पक्षता के लिये सराहना की गई है, हालाँकि चुनावी प्रणाली में कुछ कमियाँ भी सामने आई हैं। इस संबंध में देश में चुनाव सुधारों की आवश्यकता पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

While conduct and outcome of elections over the years have been appreciated for fairness, some shortcomings have also emerged in the electoral system. In this regard discuss the need for electoral reforms in the country. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

निष्पक्ष चुनाव, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आधार है। यही कारण है कि संविधान के अनु० 324 के तहत निष्पक्ष निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है।

चुनाव आयोग की भूमिका की सराहना

- EVM के प्रयोग से बूथ कैप्चरिंग जैसी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण लगा है
- चुनाव प्रक्रिया व मतगणना सुचारु रूप से संचालित हुए हैं
- चुनाव की प्रक्रिया को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाया गया है
  Ex- टीएन शेषन (पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त) ने इस क्षेत्र में प्रभावी कार्य किए है
- एक साथ चुनाव कराने की संकल्पना सामने आयी है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

चुनाव प्रक्रिया की कमियां

- चुनाव मे धन बल के प्रयोग संबंधी विवाद सामने आये है
- राजनीति का अपराधीकरण (ADR की रिपोर्ट के अनुसार 43% सदस्यों (सांसदों) पर आपराधिक मुकदमें दर्ज है)
- मॉडल कोड आफ कंडक्ट के उल्लंघन के विरुद्ध चुनाव आयोग की शक्ति सीमित है
- चुनाव वित्त पोषण मे अपारदर्शिता
- EVM मे छेड़छाड़ संबंधी विवाद सामने आए है

चुनाव सुधारों की आवश्यकता

- चुनाव संबंधी पोषण के संदर्भ मे पूर्व चुनाव आयुक्त ने राज्य वित्त पोषण की अनुशंसा की है
- VVPAT के इस्तेमाल को प्रभावी बनाना

Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

- चुनाव आयोग के मॉडल कोड आफ कंडक्ट के संदर्भ मे कार्यवाही की शक्ति को बढ़ाया जाए
- ई वोटिंग को प्रभावी बनाया जाए
- मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़कर फर्जी मतदान को रोका जा सकता है
- चुनाव के दौरान अवैध गतिविधियों के संदर्भ मे पृथक फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किया जा सकता है
- एक साथ चुनाव को अपनाया जा सकता है

चुनाव सुधार लोकतंत्र मे शुचिता को बढ़ावा देता है। इंद्रजीत गुप्ता समिति व द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा के आधार पर चुनाव सुधार कर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकता है

Copyright – Drishti The Vision Foundation

14. 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति का रणनीतिक महत्त्व व्यापक क्षेत्र में विकास को आकार देने की भारत की क्षमता का एक महत्त्वपूर्ण कारक बना रहेगा। परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 15

The strategic significance of the neighborhood-first policy will remain a key factor in India's ability to shape developments in the wider region. Examine. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

भारत ने अशोक की शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की रणनीति के तहत पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए नेबरहुड फर्स्ट की नीति अपनायी गयी है।

नेबरहुड नीति की आवश्यकता

- दक्षिणी एशियाई देशों के सामाजिक आर्थिक हित परस्पर जुड़े हुए हैं
  - जैसे उदाहरण- नेपाल ऊर्जा उत्पादक है तो भारत आयातक
- दक्षिण एशियाई देशों की सांस्कृतिक पहचान एक समान है
- भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए बांग्लादेश व म्यांमार के साथ संबंध प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं
- भारत व द. एशिया के संगठित अपराधों पर नियंत्रण के लिए, ड्रग

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti दृष्टि The Vision

व मानव तस्करी रोकने के लिए सहयोग व समन्वय की आवश्यकता है।

- हिंद महासागर की सुरक्षा व शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए श्रीलंका व मालदीव, मॉरीशस के साथ सहयोग आवश्यक है
- चीन की आक्रमक नीतियों व ऋणजाल की नीति का प्रतिसंतुलन करना
- अन्य देशों से कनेक्टिविटी व ऊर्जा सुरक्षा के लिए विस्तारित नेबरहुड की नीति अपनायी गयी है, इसी क्रम में लुक वेस्ट की नीति सामने आयी है

भारत के प्रयास

- गुजराल डॉक्ट्रिन के तहत पाकिस्तान चीन को छोड़कर अन्य देशों को एकतरफा छूट प्रदान की गई है
- नेपाल के अरुण परियोजना को स्थापित किया जा रहा है
- बांग्लादेश के रूपपुर परमाणु संयंत्र में सहयोग किया जा रहा है

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

- श्रीलंका संकट के दौरान $4 बिलियन की क्रेडिट व खाद्य व दवा आपूर्ति की गई है।
- विस्तारक को प्रभावी बनाया जा रहा है
- सार्क सैटेलाइट के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया है
- BBIN के द्वारा परिवहन साधनों का विकास किया जा रहा है
- अफगानिस्तान को आपदा के दौरान खाद्य आपूर्ति की गई है

चुनौतियां → भारत-पाक तनावपूर्ण संबंध
→ भारत द्वारा परियोजना निर्माण डिलीवरी में देरी
→ जातीय संघर्ष
→ म्यांमार - रोहिंग्या संकट
→ नदी जल विवाद
→ चीन की आक्रमक नीतियां
→ सार्क की असफलता

दक्षिण एशिया में स्थापित भारतीय विकास के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए भारत ने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को प्राथमिकता दी है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

drishti दृष्टि The Vision

15. भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति पर चर्चा कीजिये और भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिये। (250 शब्द) 15

Discuss the constitutional position and explain the process of election of the President of India. (250 words) 15

भारतीय संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख (Art 52) है, जो संविधान के रक्षक की भूमिका निभाता है, कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं।

राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति

Art-60 के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वाधिक सर्वोच्च पद माना गया है,
Art-58 के तहत योग्यता का निर्धारण
Art-72 के क्षमादान की शक्ति
Art-75 के तहत प्रधानमंत्री के नियुक्ति की शक्ति दी गई है।

भारतीय संसदीय परंपरा में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करना पड़ता है (Art-73/74)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

- राष्ट्रपति को सत्र आहूत व ~~विसर्जन~~ सत्र समापन का अधिकार है किंतु यह भी मंत्रीमंडल के परामर्श पर ही निर्भर है
- वह मंत्रियों की नियुक्ति करता है (प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर)
- वह महालेखापरीक्षक, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, वित्त आयोग, चुनाव आयोग आदि के प्रमुखों की नियुक्ति करता है
- इस तरह राष्ट्रपति संवैधानिक तो प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख है

<u>राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया</u>

- चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया संपन्न करायी जाती है
- वर्तमान राष्ट्रपति के पद समापन से पहले चुनाव आवश्यक है
- इसके चुनाव की प्रक्रिया अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा होता है जहां चुने हुए

Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

प्रतिनिधि चुनाव में भाग लेते हैं

- इसके लिए निर्वाचक मंडल का गठन होता है
  - राज्य विधानमंडल (विधानसभा) के निर्वाचित सदस्य
  - संसद के निर्वाचित सदस्य
    - मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं
- यह चुनाव प्रक्रिया एकल मतदान की संक्रमणीय पद्धति से संपन्न होता है
- निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार को कुल वोटों के आधे से एक अधिक मत को प्राप्त करना आवश्यक होता है (50%+1)
- उम्मीदवार की योग्यता का निर्धारण अनु० 58 के द्वारा होता है
- उम्मीदवार का लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए

राष्ट्रपति का पद संसद की गतिविधियों व कार्यपालिका के संतुलन के लिए आवश्यक है, यह राज्य संघ के बीच संतुलन का भी प्रमुख माध्यम है

Copyright – Drishti The Vision Foundation

16. सीमा पार जल विवाद भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच हमेशा से विवाद का एक विषय रहा है। भारत में सीमा पार नदी प्रबंधन से संबद्ध मुद्दों की चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

Transboundary water disputes have always been a bone of contention between India and its neighboring countries. Discuss the issues associated with Transboundary River management in India. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारत व पड़ोसी देश के बीच प्रगाढ़ संबंध दक्षिण एशियाई विकास के लिए महत्वपूर्ण है, किंतु नदी जल विवाद संबंधो को कमजोर बनाता है।

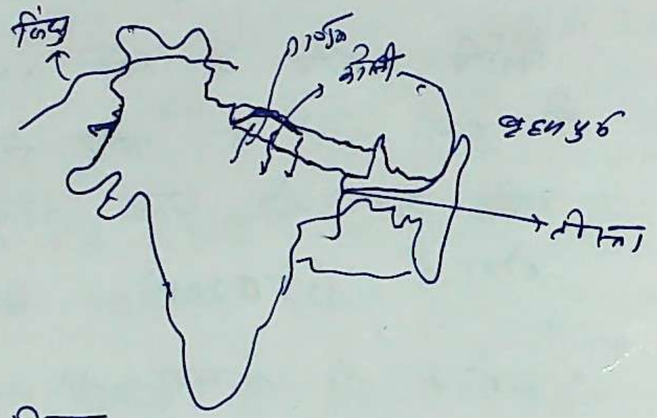

नदी जल विवाद

① सिंधु नदी जल विवाद

भारत व पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी जल का विवाद तनाव का प्रमुख कारण है, इसके लिए विश्व बैंक की मध्यस्थता से सिंधु बोर्ड का गठन हुआ है,

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

सिंधु नदी जल बंटवारा — सिंधु, झेलम, चेनाब } पाकिस्तान; रावी, व्यास, सतलज } भारत को 3 नदियां

② तीस्ता जल विवाद

तीस्ता जल विवाद, भारत बांग्लादेश संबंधो को प्रभावित करता है, यह बांग्लादेश के कृषि व जलापूर्ति के लिए आवश्यक है तो पश्चिम बंगाल के लिए तीस्ता नदी से जुड़ते हैं

③ नेपाल से विवाद

- गण्डक व कोसी नदियों के तहत मानसून के दौरान छोड़े गए जल से बिहार व पूर्वी यूपी में बाढ़ की स्थिति तनाव उत्पन्न करती है

④ ब्रह्मपुत्र के तट पर चीन द्वारा निर्मित किया जा रहा बांध पूर्वोत्तर भारत के पारिस्थितिकी व सुरक्षा उपाय पर संकट उत्पन्न कर सकता है

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

सीमापार नदी प्रबंधन से संबंधित मुद्दे_

- दक्षिणी एशिया में कृषि विकास के लिए नदी जल का तार्किक विभाजन आवश्यक है
- व नदी पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण का मुद्दा है
- ऊर्जा उत्पादन के लिए बांधों का निर्माण भी प्रमुख मुद्दा है, भारत द्वारा चेनाब व झेलम पर निर्मित बांधो की पाकिस्तान आलोचना करता है
- क्षेत्रीय विकास व आपसी संबंधो की प्रभावशीलता के लिए नदी जल प्रबंध आवश्यक है
- व चीन की आक्रामक रणनीतियों को प्रतिसंतुलित करने में
- बाढ़ व सूखे की दशा में सीमा पार नदी जल प्रबंधन महत्वपूर्ण हो जाता है

सीमापार जल प्रबंधन दक्षिण एशिया में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व आधारित संबंधों का निर्धारक है, भारत ने नेपाल व बांग्लादेश के साथ नदी जल विवादों के समाधान का प्रयास किया है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

17. संघर्षी संघवाद उस संविधान के लिये अभिशाप है जो केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और सहकारिता की इच्छा रखता है। चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

Combative federalism is anathema to the Constitution which prescribes cooperation and collaboration between the Centre and the States. Discuss. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

संघवाद, राज्य व केन्द्र की सहयोगात्मक भूमिका के द्वारा जनकल्याण को प्रभावी बनाने व आर्थिक विकास को तीव्र करने की संकल्पना है।

जबकि संघर्षी संघवाद राज्य व संघ तथा राज्यों के बीच तनाव को दर्शाता है।

संघर्षी संघवाद संविधान के लिए अभिशाप_

① अनु० 1 के तहत राज्यों के संघ की संकल्पना सहयोग पर आधारित है संघर्ष पर नहीं।

② 7वीं अनुसूची के तहत राज्य, संघ व समवर्ती सूची के बीच विषयों का विभाजन किया गया है, जहां राज्य व संघ आपस एवं समकक्ष है, ऐसे में संघर्ष संवैधानिक गतिरोध को बढ़ावा दे सकता है

③ राज्य - राज्य सूची पर कानून बनाने

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

व संघ संघ सूची पर कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, ऐसे में संघर्ष की स्थिति देश में कानूनी जटिलता को उत्पन्न कर सकता है)

- अखिल भारतीय सेवा की नियुक्तियां केंद्र द्वारा किया जाता है तो राज्यो द्वारा पदस्थापना, ऐसे में राज्य संघ विवाद केंद्रीय स्तर पर अधिकारियों की कमी को जन्म दे सकता है

• GST परिषद में संघर्ष की स्थिति से ईज आफ डूइंग बिजनेस कमजोर होगा
  ↳ निवेश (↓) → विकास दर (↓)

• प्रतिस्पर्धी व सहयोगात्मक संघीय शासन की प्रभावशीलता —

- देश में ईज आफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा
- कानूनों की जटिलता कम होगी
- कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ेगी
- नदी जल विवाद जैसे राजनीतिक मुद्दों

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

का निर्धारण प्रभावी होगा।

•

सहयोगात्मक संघवाद के उपाय

↳ नीति आयोग की भूमिका (नीति
↳ क्षेत्रीय राज्य परिषद का गठन
↳ स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन
↳ विषयों का बंटवारा → स्पष्ट अनुसूची
↳ GST परिषद में राज्यों को 2/3 बहुमत

सहयोगात्मक व सहयोगी संघवाद भारत की संवृद्धि व विकास के लिए अपरिहार्य है, जो लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर स्थापित करता है सरकारिया व पुंछी आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर इसे प्रभावी बनाया जाना चाहिए

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

18. देश में कारागार प्रशासन के समक्ष विद्यमान संकटकारी मुद्दों पर चिंतन करने की आवश्यकता है। परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 15

There is a need to reflect upon the issues plaguing the prison administration in the country. Examine. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारत में लगभग 4.5 लाख कैदी जेलों में बंद हैं, जो मानकों की संख्या से ज्यादा है

कारागार प्रशासन के मुद्दे

- कारागारों की क्षमता से अधिक कैदी
- कारागारों में विचाराधीन कैदियों की संख्या लगभग 75% है,
- कारागारों के आधुनिकीकरण का अभाव
- शौचालय व सुधार गृहों की कमजोर स्थिति
- कारागारों में कर्मचारियों के प्रशिक्षण का अभाव

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

- कारागार प्रणाली सुधारों को प्रभावी नहीं बना पायी है

सुधार – मानवाधिकार आयोग की अनुशंसा को अपनाया जाए
- ओपन जेल की अवधारणा को अपनाया जाए
- आधुनिकीकरण किया जाए
- सुधार गृहों को प्रभावी बनाया जाए
- विचाराधीन कैदियों को बेल देने की प्रक्रिया सरल की जाए.
- कैदियों को कौशलीकरण से जोड़ा जाए.
- आपराधिक सुधार की न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाए।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कारागार कैदियों के सुधार का स्थान होना चाहिए, इसके लिए कारागारों के आधुनिकीकरण के साथ मानवीय सुधारों को गति लाने की आवश्यकता है

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

19. शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के संगठनात्मक ढाँचे की व्याख्या कीजिये और चर्चा करिये कि SCO की सदस्यता भारत के लिये कैसे प्रासंगिक है? (250 शब्द) 15

Explain the organizational structure of Shanghai Cooperation Organization (SCO) and discuss how SCO's membership is relevant to India? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

शंघाई सहयोग संगठन मध्य एशिया की स्थिरता व आर्थिक विकास को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से गठित संगठन है, जिसकी स्थापना 1995 में चीन के नेतृत्व में की गई थी।

संगठन व उद्देश्य –

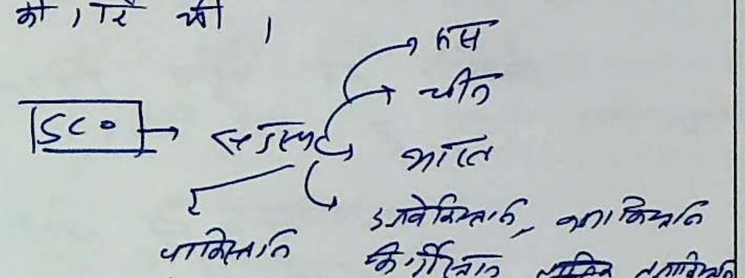

- SCO का गठन चीन के नेतृत्व में हुआ
- यह RATS (आतंकवाद रोधी तंत्र) के माध्यम से क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावी बनाता है
- यह सदस्य देशों के बीच आर्थिक गतिविधियों को प्रभावी बनाता है

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

- यह सीमा पार कनेक्टिविटी को प्रभावी बनाता है

भारत के हित

- यह भारत को मध्य एशिया व रूस तक कनेक्टिविटी प्रदान करता है
- यह मध्य एशियाई देशों के प्राकृतिक संसाधनों तक पहुँच सुनिश्चित करता है
  - कजाकिस्तान से यूरेनियम की आपूर्ति
  - तजाकिस्तान से और [illegible] खनिज का विकास होने के अवसर हैं
- यह अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण कॉरिडोर तक संपर्क प्रभावी बनाता है
- यह अफगानिस्तान मे तालिबानी शासन के उदय को प्रभावी रूप से नियंत्रित कर सकता है

Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

- भारत रूस के साथ मिलकर चीन-पाक गठजोड़ पर नियंत्रण रख सकता है
- चीन के साथ संवाद को बढ़ावा फलतः सीमा तनाव में कमी आ सकती है

चुनौतियां:

- वर्तमान मे चीन-रूस का गठजोड़ व उसमे पाकिस्तान की सहभागिता
- भारत-चीन सीमा विवाद
- पश्चिमी देश इसे चीनी नाटो कहते हैं
- चीन की आक्रामक नीतियां
- चीन के BRI प्रोजेक्ट की आक्रामक नीतियां

भारत की SCO की सदस्यता को केवल [illegible] नहीं माना जा सकता है, भारत ने समानांतर संबंधों की रणनीति के तहत रूस चीन के साथ पश्चिमी देशों के साथ संबंध बनाए हैं भारत SCO का प्रयोग ऊर्जा सुरक्षा व भूसामरिक चुनौतियों के प्रतिसंतुलन के रूप कर सकता है

Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

20. न्यायपालिका पर वादों/मामलों के भार को कम करने के लिये ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की गई है, लेकिन इसने न्याय प्रणाली में कई चुनौतियों को जन्म दिया है। समालोचनात्मक चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15
Tribunals are established to reduce the case load of the judiciary but it has given rise to multiple challenges in justice system. Critically discuss. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारतीय न्यायपालिका के समक्ष लगभग 4.5 करोड़ मामले लंबित हैं, इसी तरह न्यायप्रक्रिया को विशेषज्ञता व वैकल्पिक तंत्र स्थापित करने के लिए संविधान के अनु० 324 के तहत ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है

ट्रिब्यूनल → 42वां संविधान संशोधन
- 323(A) → प्रशासनिक ट्रिब्यूनल
- 323(B) → अन्य ट्रिब्यूनल

महत्व → न्यायपालिका के भार में कमी आएगी।
- प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, फलतः वादी-प्रतिवादी प्रक्रिया के स्थान पर सक्रियप्रक्रिया अपनायी जा सकती है।
- वैकल्पिक न्यायिक तंत्र की स्थापना
- विशेषज्ञ न्याय निर्णयन
- (4) विशेषज्ञों के साथ विषयों के जानकार की

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

शामिल
- मामलों का तीव्र निपटारा संभव है

चुनौतियां
- इनके फैसले लागू नहीं हो पाते हैं
- इनके विरुद्ध Art-136 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच संभव हो जाती है
- इनके फैसले लागू करने में प्रशासनिक चुनौतियां विद्यमान हैं
- NGT के फैसले कई बार लागू नहीं हो पाते हैं

भविष्य की राह

- ट्रिब्यूनल को प्रभावी बनाने के लिए उनके निर्णयों को लागू किया जाना आवश्यक किया जाए

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

→ अपीलीय प्राधिकरण को प्रभावी बनाया जाए।

→ इनके फैसलों को उच्चतम न्यायालय के फैसलों के समान मान्यता हो जाए ॥

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

Space for Rough Work

(रफ कार्य के लिये स्थान)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation